किसानों की सब्सिडी में कमी करेगी सरकार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दिख सकता है असर

कन्हैया लोधी

भोपाल, 13 फरवरी. वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए मप्र का बजट तैयार करने का सिलसिला अब अंतिम चरणों में है. बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ ही कैबिनेट के सामने भी प्रेजेंटेशन दे दिया गया है.

अब बजट प्रिंट कराने से पहले उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस बीच बजट को लेकर जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर राज्य सरकार बजट में ज्ञान पर ही फोकस करेगी. ज्ञान यानी राज्य सरकार के चार मिशन, जिसमें गरीब, युवा, किसान और नारी कल्याण शामिल है. नए बजट में वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर कसावट देखने मिलेगी. सबसे बड़ी बात ये कि लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह खर्च होने वाली बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए अब इस मद में राशि का इंतजाम करने के लिए किसानों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को कम करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए किसानों को अब परंपरागत बिजली के बजाय सोलर से बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

दरअसल नए वित्तीय वर्ष में किसानों को बिजली पर मिलने वसाली सब्सिडी बढ़कर लगभग 27 हजार करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए नए बजट में लगभग 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जरूरत पड़ेगी. इस तरह इन दोनों ही योजनाओं पर ही सरकार को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये बड़ी राशि है. ऐसे में सरकार ने किसानों को मिल रही सब्सिडी का बोझ सरकार के कंधे से कम करने के लिए नया रास्ता निकाल लिया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू की गई है.

इस योजना के तहत कृषि पंप वाले एक लाख किसानों को परंपरागत बिजली के बजाय सोलर की बिजली से पलेवा करने के लिए उन्हें कनेक्शन दिए जाएंगे. सबसे पहले फोकस अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं पर किया जाएगा, उसके बाद फिर स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को सोलर में शिफ्ट करने की कोशिश होगी. यदि राज्य सरकार की योजना परवान चढ़ी तो वर्ष 2026-27 की अवधि में राज्य सरकार पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है. इस बचत राशि को लाड़ली बहना सहित दूसरी नगद योजनाओं पर खर्च करने में उपयोग लाया जा सकेगा. वैसे भी राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसानों को समर्पित किया है. ऐसे में न तो किसानों को कोई नाराजगी होगी और न ही बहनों को प्रसन्न रखने में कोई परेशानी होगी.

वर्ष के अंत तक1750 प्रतिमाह करेगी सरकार

वित्त विभाग को नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन की ज्यादा इसलिए भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर से पहले प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर 1750 रुपए की जा सकती है. जिस तरह भाजपा ने संकल्प पत्र में जाहिर किया था कि बहनों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देंगे, इसके लिए ये जरुरी है कि सरकार योजना की राशि में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी जरुर करेगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक वर्ष दीपावली के आसपास बहनों को 1500 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 1750 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है.

रावसे के 24 अधिकारियों की आईएफएस के रूप में पदोन्नति

भोपाल, 13 फरवरी. मध्यप्रदेश में राज्य वन सेवा (रावसे) के 24 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस संबंध में स्वीकृति के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिकारियों का चयन वर्ष 2023 और 2024 को आधार मानकर किया गया है.

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में माधव सिंह मौर्य, ज्योति मुड़िया, हरीश चंद्र बघेल, संतोष कुमार रणशोर, शीतल प्रसाद शाक्य, बालक राम सिरसाम, भानु प्रकाश बाथम, रामकिशन सोलंकी, रेशम सिंह धुर्वे, मानसिंह मरावी, सुंदर दास सोनवानी और योहान कटारा शामिल हैं. इसके साथ ही विद्याभूषण मिश्रा, राजवेंद्र मिश्रा, अनुभा त्रिवेदी, जया पांडे त्रिपाठी, मुकेश पटेल, धीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, लाल सुधाकर सिंह, शिको राही किचोलिया, विजेंद्र खोबरागड़े, भारत सोलंकी और सुरेश कुमार को आईएफएस के रूप में पदोन्नति का लाभ मिला है.

▸ सरकार ने अधिसूचना भी जारी की

वर्तमान परिस्थितियों में लेखकों की भूमिका पर मंथन

मंदसौर। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 'वर्तमान परिस्थितियों में लेखकों के दायित्व' विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य, मीडिया की भूमिका तथा लेखकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विस्तार से विचार व्यक्त किए गए।

विशेष अतिथि एवं संगठन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश जोशी ने संसद की कार्यवाही और समकालीन राजनीतिक आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संसदीय गरिमा निरंतर क्षीण हो रही है। उन्होंने निशिकांत दुबे का उल्लेख करते हुए शैक्षणिक व वैचारिक स्तर पर गिरावट की ओर संकेत किया तथा कहा कि सत्ता का दबाव अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका तक में महसूस किया जा रहा है। श्री जोशी ने कहा कि अव्यवस्थाएँ पूर्व में भी थीं, किंतु 2014 के बाद वे अधिक विकराल रूप में उभरी हैं। मीडिया पर घटते भरोसे का उल्लेख करते हुए उन्होंने सशक्त जन-आंदोलन और वैचारिक नेतृत्व की आवश्यकता बताई।

प्रलेसं राज्य सचिव मंडल सदस्य असअद अंसारी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जुड़े विवादित वीडियो प्रकरण पर कहा कि संवैधानिक शपथ, डिजिटल जवाबदेही और प्रशासनिक नैतिकता—तीनों की कसौटी पर हैं। उन्होंने कहा कि यदि पोस्ट अनधिकृत थी तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में स्नढ्डक्रदर्ज कर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वप्निल ओझा ने 'मोहम्मद दीपक' प्रकरण के संदर्भ में कहा कि आज पहचान और नाम के आधार पर जो सामाजिक संकुचन पैदा किया जा रहा है, वह नागरिक स्वतंत्रता के लिए चुनौती है। उन्होंने लेखकों से निर्भीक होकर संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और मानवीय समानता के पक्ष में लेखन करने का आह्वान किया।

संगठन के कोषाध्यक्ष ब्रजेश आर्य ने कहा कि अनेक घटनाओं से कतिपय संगठनों का सांप्रदायिक एजेंडा उजागर हो रहा है, इसलिए लेखकों का दायित्व है कि वे तथ्याधारित लेखन से नागरिक चेतना को सशक्त करें। वरिष्ठ सदस्य प्रकाश गुप्ता ने व्यापारी से विद्यार्थी तक व्याप्त भय के वातावरण को रेखांकित करते हुए कहा कि इस मन:स्थिति की अभिव्यक्ति साहित्य में होना आवश्यक है।

उज्जैन में ट्रेनों को वापस मोड़ने की जरुरत नहीं होगी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेल मंत्रालय द्वारा उज्जैन बायपास लाइन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार माना है. कुल 8.60 किमी की नईखेड़ी-चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली इस लाइन के प्रारंभ होने से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा. इससे उज्जैन से ट्रेनों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रेनों में विलंब नहीं होगा. यह व्यवस्था सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगी. उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल द्वारा 189.04 करोड़ रुपये की इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है.

20,098 किसानों ने कराया पंजीयन

07 मार्च तक खुला रजिस्ट्रेशन

भोपाल, 13 फरवरी. रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए अब तक 20,098 किसानों ने पंजीयन करा लिया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि वे 7 मार्च तक पंजीयन अवश्य करा लें.

उन्होंने कहा कि किसान हित में पंजीयन प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाया गया है तथा प्रदेश में कुल 3,186 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं. केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक है.

अभी तक इंदौर संभाग में 4,084, उज्जैन में 9,524, ग्वालियर में 476, चंबल में 123, जबलपुर में 788, नर्मदापुरम में 900, भोपाल में 3,602, रीवा में 68, शहडोल में 83 और सागर में 450 किसानों ने पंजीयन कराया है. पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों तथा सहकारी समितियों/विपणन संस्थाओं के माध्यम से की गई है.

इसके अलावा, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और साइबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है. जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी तथा ग्राम पंचायतों में सूचना पटल और मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेश में कुल 17 नकल प्रकरण हुए दर्ज

▸ राजधानी में 6 मामले आए प्रकाश में

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 13 फरवरी. माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2026 का प्रश्नपत्र शुक्रवार को प्रदेशभर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ.

लेकिन इस बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली इंटरमीडियट परीक्षा में कुल 17 नकल प्रकरण सामने आए. इनमें जिला भोपाल में 6 मुरैना में 6, मंदसौर, इंदौर, बैतूल, जबलपुर और सिवनी में 1-1 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जबकि हाईस्कूल परीक्षा में एक भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ.

बोर्ड प्रशासन का कहना है कि सभी केंद्रों पर उड़नदस्तों की सतत निगरानी और सख्त दिशा निर्देशों के कारण स्थिति नियंत्रण में है और परीक्षाएं सुचारु रूप से चल रही हैं. नकल मुक्त परीक्षा को लेकर मंडल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. वहीं सख्ती के बीच विद्यार्थियों ने भी अनुशासन का परिचय दिया. प्रदेशभर में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने से शिक्षा मंडल ने संतोष व्यक्त किया है.

16 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा

बता दें इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में लगभग 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जबकि हायर सेकेंडरी परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हैं. आगामी परीक्षा में हाईस्कूल के छात्रों का अंग्रेजी विषय और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों का रसायन शास्त्र का प्रश्नपत्र आयोजित किया जाएगा.

शिवराज ने दिग्विजय को धन्यवाद कहा

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में मूंग की फसल के सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें मेरे संसदीय क्षेत्र की इतनी चिंता है.

श्री चौहान ने श्री सिंह के संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि सीहोर, रायसेन और हरदा में मूंग की भरपूर पैदावार हो रही है. इसलिए उसके लिए अलग से क्लस्टर की जरूरत नहीं है. मूंग की फसल की वृद्धि के प्रयास हमारी सरकार ने ही किए थे और आज भी हम कर रहे हैं.

मध्यप्रदेश में ठंड से काफी राहत

30 डिग्री पार पहुंचा दिन का तापमान

पश्चिमी विक्षोभ का असर सीमित

भोपाल, 13 फरवरी. मध्य प्रदेश में अब सर्दी का असर लगातार कम होता नजर आ रहा है. प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम के इस बदलाव से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ठंड अब विदाई की ओर है.

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे. इनका मुख्य प्रभाव पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां बर्फबारी और वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि मध्य प्रदेश में इन सिस्टम का असर सीमित रहने की संभावना है. इसके चलते हल्की ठंड का एक छोटा दौर महसूस हो सकता है, लेकिन कड़ाके की सर्दी लौटने की संभावना नहीं है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.

अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में यह सामान्य से 1.6 से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. अन्य संभागों में तापमान सामान्य स्तर पर बना रहा. न्यूनतम तापमान में भी खास बदलाव नहीं हुआ. इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों में रात का तापमान सामान्य से 1.9 से 2.4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. वहीं उज्जैन और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 3.3 डिग्री तक अधिक रहा, जो इस समय के लिए उल्लेखनीय वृद्धि मानी जा रही है.

डेढ़ करोड़ में हुआ विवाद समाप्त

फिल्मी अंदाज में तलाक का समझौता

भोपाल, 13 फरवरी. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पारिवारिक विवाद का अनोखा मामला सामने आया है, जिसकी तुलना वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म जुदाई से की जा रही है. हालांकि यह मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत आपसी सहमति से सुलझाया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय एक केंद्रीय सरकार के अधिकारी का अपनी 54 वर्षीय सहकर्मी से प्रेम संबंध हो गया. इस संबंध के कारण उनके दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ गया और मामला कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया. दंपत्ति की दो बेटियां भी हैं, जिन पर पारिवारिक विवाद का प्रभाव पड़ रहा था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ आगे नहीं रहना चाहता और सहकर्मी के साथ जीवन बिताना चाहता है. इस पर पत्नी ने तलाक के बदले एक डुप्लेक्स फ्लैट और 27 लाख रुपये नकद की मांग रखी.

बताया गया है कि कुल मिलाकर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद दंपत्ति ने आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया पूरी की. मामला सामने आने के बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी इसे फिल्मी कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है.

सौर पंप योजना पर उठे गंभीर सवाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 फरवरी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. मुकेश नायक ने शुक्रवार को राज्य सरकार की सौर पंप योजना पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी का वादा किया गया, लेकिन वास्तविकता में उन्हें भारी बैंक ऋण के बोझ तले धकेल दिया गया है.

नायक ने आधिकारिक ऋण स्वीकृति पत्रों और बैंक दस्तावेजों का हवाला देते हुए योजना की वित्तीय संरचना को 'गंभीर रूप से चिंताजनक' बताया. पार्टी द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार सौर पंप की कुल परियोजना लागत 4,04,475 रुपये दर्शाई गई है, जबकि वास्तविक सब्सिडी मात्र 1,09,537 रुपये दर्ज है. किसानों से 41,537 रुपये मार्जिन मनी के रूप में जमा कराए गए और उनके नाम पर 2,53,402 रुपये का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया. यह ऋण 8.30 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया है, जिसकी 84 महीनों तक लगभग 3,987 रुपये मासिक किस्त निर्धारित की गई है. चूक की स्थिति में दंडात्मक ब्याज का भी प्रावधान है.

किसानों पर ढाई लाख से अधिक का ऋण क्यों?

डॉ. नायक ने सवाल किया कि यदि 90 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है तो किसानों पर ढाई लाख रुपये से अधिक का ऋण क्यों डाला गया. उन्होंने वास्तविक सब्सिडी प्रतिशत स्पष्ट करने और इसे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने की मांग की. साथ ही पूछा कि क्या किसानों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 10 प्रतिशत अंशदान जमा करने के बाद भी उन्हें भारी बैंक देनदारी उठानी पड़ेगी. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या बैंकों के माध्यम से सौर कंपनियों को पूरा भुगतान पहले ही जारी कर दिया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस समारोह 16 को

भोपाल. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग का 32वां स्थापना दिवस समारोह 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जायेगा. समारोह के मुख्य अतिथि भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी. रावत होंगे. रावत वन नेशन-वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की भूमिका विषय पर व्याख्यान देंगे. पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम स्थानीय निर्वाचन में सुधार की चुनौतियां विषय पर उद्बोधन देंगे. नरेन्द्र कुमार सिंह जमीनी लोकतंत्र में पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव विषय पर और एडवोकेट सिद्धार्थ सेठ स्थानीय निर्वाचन में न्यायालयीन सबक विषय पर उद्बोधन देंगे.

अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती का हुआ खुलासा

अंतरराज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार

मुरैना, 13 फरवरी. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह कस्बे में राबिया किन्नर के घर हुई लगभग 40 लाख रुपये की सशस्त्र डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर तथा एक लाख 49 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार 16 और 17 जनवरी की मध्यरात्रि अंबाह कस्बे की दोहरी रोड स्थित बजरंग कॉलोनी निवासी राबिया किन्नर के घर में हथियारबंद डकैतों ने धावा बोल दिया था. बदमाशों ने राबिया और उनके अन्य किन्नर साथियों को हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवर और नगदी सहित करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति लूट ली थी. घटना के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में पांच विशेष टीमें गठित की गई थीं. पुलिस ने वारदात के तरीके का विश्लेषण करते हुए 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साक्ष्य एकत्र किए. इसके आधार पर राजस्थान और उत्तरप्रदेश में दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

राजनीति ▸ कथित लाठीचार्ज मामले में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे

जीतू पटवारी ने प्रदर्शन में की शिरकत

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 फरवरी. शहडोल में स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों पर जिला प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.

विपक्ष ने भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता और दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में भाजपा सरकार प्रदेशवासियों को एक गिलास स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध कराने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों, विशेषकर पानी, की मांग करती है तो सरकार समाधान देने के बजाय लाठियां चलवाती है, जो लोकतांत्रिक शासन नहीं बल्कि तानाशाही का उदाहरण है. उन्होंने दावा किया कि शहडोल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है.

▸ सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

▸ लाठीचार्ज के बाद गर्माई राजनीति

युवाओं में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और अवैध रेत खनन जैसे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया. पटवारी ने सरकार पर कानून-व्यवस्था चरमराने और प्रशासन के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को 'सड़क से सदन तक' उठाएगी और कथित ज्यादतियों का हिसाब लेकर रहेगी.

5 लापता नाबालिग सकुशल मिले

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 फरवरी. मध्यप्रदेश पुलिस ने नरसिंहपुर और शिवपुरी जिलों में दो अलग-अलग कार्रवाइयों के दौरान पांच लापता नाबालिग बच्चों को सकुशल दस्तयाब कर सराहनीय सफलता हासिल की है.

यह कार्रवाई बाल सुरक्षा के मामलों में पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और पेशेवर दक्षता को रेखांकित करती है. नरसिंहपुर जिले में 10 फरवरी को थाना गोटेगांव क्षेत्र से 9 और 8 वर्ष की दो बालिकाओं के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सघन तलाश शुरू की. पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश के नेतृत्व में चार विशेष टीमों का गठन किया गया. टीमों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खोजबीन की तथा सीसीटीवी फुटेज की भी गहन जांच की.

लगातार प्रयासों के बाद दोनों बालिकाएं ग्राम कमती सेमरावारी के खेत में एक पेड़ के पास झाड़ियों में सुरक्षित मिलीं. पूछताछ में सामने आया कि परिजनों की डांट के डर से वे स्वयं छिप गई थीं. बाद में उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. इसी प्रकार शिवपुरी जिले में 12 फरवरी को एक हॉस्टल से 14, 15 और 17 वर्ष के तीन बालकों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई.